

राजस्थान / 02

कौन आवेदन कर सकता है?

पहले आपूर्तिकर्ता, आपूर्ति और दस्तावेजों की जांच करें।

सूक्ष्म और लघु उद्यम

MSMED अधिनियम का अध्याय V पात्र सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ताओं को संरक्षण देता है। केवल MSME होने से मध्यम उद्यम को यह संरक्षण नहीं मिलता। मंत्रालय के समाधान विवरण के अनुसार वैध उद्यम (Udyam) पंजीकरण जरूरी है।

वर्तमान श्रेणी	निवेश की अधिकतम सीमा	टर्नओवर की अधिकतम सीमा
सूक्ष्म	2.5 करोड़ रुपये	10 करोड़ रुपये
लघु	25 करोड़ रुपये	100 करोड़ रुपये

दोनों मानदंड लागू होते हैं। ये सीमाएं 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हैं। पुरानी आपूर्ति के लिए उस समय लागू श्रेणी और पंजीकरण की समीक्षा करें।

इन तीन बातों पर विशेष ध्यान दें

- पंजीकरण की तारीख:** पहले के अनुबंध या आपूर्ति की कानूनी समीक्षा जरूरी है। पूर्व सर्वोच्च न्यायालय निर्णयों में सीमाएं थीं; NBCC (2025) में मुद्दा बड़ी पीठ को भेजा गया। नया पंजीकरण पुराने दावे को स्वतः पात्र नहीं बनाता।
- कारोबार की गतिविधि:** केवल खुदरा या थोक व्यापार करने वाले उद्यम, उद्यम पंजीकरण के आधार पर विलंबित भुगतान का लाभ न मानें। मंत्रालय के अनुसार व्यापारियों के समावेशन का लाभ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण तक सीमित है।
- प्रमाण और तारीखें:** बकाया राशि, स्वीकृति, तय उधार अवधि, भुगतान और आपत्तियां पहचानें। पुराने दावों में परिसीमा यानी दावा करने की कानूनी समय सीमा की तत्काल जांच कराएं।

आपूर्तिकर्ता राजस्थान में, खरीदार दूसरे राज्य में?

धारा 18(4) के अनुसार आपूर्तिकर्ता के क्षेत्र की परिषद भारत में कहीं भी स्थित खरीदार के मामले पर कार्यवाही कर सकती है। पंजीकृत स्थान और वर्तमान परिषद आवंटन की पुष्टि करें।

आधिकारिक स्रोत: [1] · [2] · [3] · [7] · [9]

राजस्थान / 03

भुगतान की समय सीमा और समाधान की प्रक्रिया

कानूनी लक्ष्य, वसूली की गारंटी नहीं है।

नियम	इसका अर्थ
लिखित भुगतान समझौता नहीं	स्वीकृति या मानी गई स्वीकृति से 15 दिन पूरे होने के बाद आने वाले नियत दिन से पहले भुगतान देय है।
लिखित भुगतान समझौता है	तय तारीख लागू होगी, पर स्वीकृति या मानी गई स्वीकृति से अधिकतम 45 दिन। पहले तय की गई देय तारीख भी महत्वपूर्ण है।
देरी पर ब्याज	धारा 16 के अनुसार RBI बैंक दर के तीन गुने पर, मासिक चक्रवृद्धि ब्याज। यह रेपो दर का तीन गुना नहीं है।

माल मिलने या सेवा दिए जाने के 15 दिनों के भीतर लिखित आपत्ति स्वीकृति की तारीख को प्रभावित कर सकती है। केवल बिल की तारीख से कानूनी अवधि तय नहीं होती।

समाधान का क्रम

- समीक्षा और मिलान:** पात्रता, बकाया और प्रमाण की पुष्टि करें।
- मार्ग चुनकर आवेदन:** वर्तमान समाधान / ODR और राजस्थान परिषद की आवश्यकताएं जांचें; जांच और नोटिस पहुंचाने के चरण पूरे करें।
- सुलह:** परिषद या उसके द्वारा चुनी गई संस्था के माध्यम से समझौते का प्रयास होता है।
- जरूरत होने पर पंचाट (arbitration):** सुलह विफल होने पर विवाद निर्णय तक जा सकता है। इसके बाद अलग प्रवर्तन या न्यायालय की कार्यवाही हो सकती है।

कितना समय लगेगा?

धारा 18(5) संदर्भ दिए जाने से 90 दिनों में निर्णय का लक्ष्य रखती है। जांच, नोटिस, सुनवाई, चुनौती और प्रवर्तन में अधिक समय लग सकता है। सफल वसूली या 90 दिनों में भुगतान की गारंटी नहीं दी जा सकती।

आधिकारिक स्रोत: [1] · [4] · [11]

राजस्थान / 04

पहली चर्चा से पहले ये दस्तावेज जुटाएं

मजबूत दावा मूल दस्तावेजों से शुरू होता है।

- उद्यम प्रमाणपत्र और पुराने EM-II / UAM पंजीकरण, तारीखों सहित।
- खरीद आदेश, अनुबंध और लिखित भुगतान शर्तें।
- बकाया बिल और प्रत्येक बिल के अनुसार बकाया विवरण।
- डिलीवरी चालान, परिवहन प्रमाण, माल प्राप्ति या सेवा पूरी होने और स्वीकृति के रिकॉर्ड।
- खरीदार का खाता, बैंक में प्राप्त भुगतान, क्रेडिट नोट, वापसी और कटौतियां।
- ईमेल, भुगतान के आश्वासन, गुणवत्ता संबंधी आपत्तियां और शेष राशि की पुष्टि।
- खरीदार का कानूनी नाम, पता और उपलब्ध पहचान विवरण।
- कानूनी नोटिस, समझौते, मुकदमे या दिवाला कार्यवाही की जानकारी।

परामर्श में क्या सहायता मिल सकती है?

पात्रता समीक्षा, खातों का मिलान, प्रमाणों की सूची, दावा तैयार करना और प्रक्रिया का अनुवर्तन। विवादित अधिकार क्षेत्र, पुराने दावे, पंचाट, निर्णय की चुनौती या प्रवर्तन के लिए अधिवक्ता से समन्वय जरूरी हो सकता है। कार्यक्षेत्र और शुल्क अलग से तय किए जाते हैं।

गोपनीय दस्तावेज भेजने से पहले

पहले संक्षिप्त पूछताछ भेजें। गोपनीय कारोबारी रिकॉर्ड के लिए अलग से सहमत सुरक्षित माध्यम अपनाएं। सलाहकार को पासवर्ड या OTP न दें।

सीए अक्षय देया

akshaybkn@gmail.com · [WhatsApp +91 99290 89598](https://www.whatsapp.com/channel/0029089598)

[LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/catool/) · catool.co.in

स्वतंत्र परामर्श; सरकार से संबद्ध नहीं। यह सामान्य जानकारी है, किसी विशेष मामले की कानूनी राय नहीं। तैयार: 10 अक्टूबर 2026। आवेदन से पहले वर्तमान कानून और राजस्थान की प्रक्रियाएं जांचें।

आधिकारिक स्रोत: [3] · [5] · [7] · [8]

आधिकारिक पोर्टल: [समाधान](#) · [MSME ODR](#) · [राजस्थान उद्योग विभाग](#)